# राजस्थान के सरकारी स्कूलों में डिजिटल अधिगम

शोभिता राजगोपाल और मुक्ता गुप्ता

## पृष्ठभूमि

कोविड-19 महामारी एक ऐसी अप्रत्याशित घटना है जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है और विश्व की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों पर महामारी का प्रभाव बहुत व्यापक रहा है। भारत में स्कूलों और कॉलेजों के बन्द हो जाने से पूरे देश के विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं, विशेष रूप से वे विद्यार्थी जो असुरक्षित और वंचित परिस्थितियों में रहते हैं। इस संकट के जवाब में राज्य के शिक्षा मंत्रालयों ने स्कूली शिक्षा में हुए व्यवधान से उपजे मुद्दों के समाधान के लिए रणनीतियाँ बनाई हैं। डिजिटल प्रणाली आधारित दूरस्थ शिक्षा को तेज़ी से बढ़ावा दिया गया है : विद्यार्थियों तक पहुँचने के लिए एसएमएस, *व्हाट्सएप*, रेडियो और टीवी कार्यक्रमों के माध्यम से पाठ्य/वीडियो/ऑडियो सामग्री का उपयोग किया जा रहा है।

राजस्थान सरकार ने अप्रैल 2020 में *व्हाट्सएप* के माध्यम से एक ई-लर्निंग मंच, *सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट* (SMILE) की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य राज्य के सरकारी स्कूलों में नामांकित सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन कोर्स और कक्षाओं की सुविधा उपलब्ध कराना था।

यह लेख, SMILE के माध्यम से संचालित ऑनलाइन शिक्षण-अधिगम के सम्बन्ध में विद्यार्थियों और शिक्षकों के अनुभवों का विश्लेषण करता है। यह राजस्थान के विभिन्न ज़िलों के सरकारी स्कूलों में उनके साथ हुई गुणात्मक बातचीत पर आधारित है। तर्क यह है कि स्कूली शिक्षा में आए वर्तमान व्यवधान को देखते हुए, विद्यार्थियों के साथ शैक्षिक जुड़ाव जारी रखने के लिए जो भी रणनीति बनाई जाए, उसमें समता और समावेशन को ध्यान में रखना चाहिए और ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिसमें सीखने की प्रक्रिया जारी रह सके।

## सन्दर्भ

भौगोलिक रूप से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह एमपावर्ड एक्शन ग्रुप (Empowered Action Group - EAG) के तहत, निम्न सामाजिक-आर्थिक संकेतकों वाले आठ राज्यों में से एक है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा काफ़ी निवेश के बावजूद ज़मीनी हक़ीक़त यह है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समता और जेंडर से सम्बन्धित कई पुराने और प्रणालीगत मुद्दे, राज्य में शिक्षा के प्रतिफलों को प्रभावित करते हैं।

वर्तमान संकट और लॉकडाउन की बढ़ती हुई अवधि के चलते राजस्थान सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया। साथ ही कक्षा दसवीं और बारहवीं को छोड़कर सभी बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का निर्णय लिया। महामारी के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की निरन्तरता सुनिश्चित करने के लिए, ऑनलाइन शिक्षा देने की तीन नीतिगत पहल, अप्रैल और जून 2020 के बीच शुरू की गई थीं : *पहली, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट (SMILE)*, जो कि *व्हाट्सएप* के माध्यम वाला ई-लर्निंग मंच है; दूसरी, *हवा महल और शिक्षा वाणी* – यह दोनों रेडियो आधारित अधिगम पहल हैं और; तीसरी, *शिक्षा दर्शन*, जो यूनिसेफ़ और Ekcovation (एक सामाजिक अधिगम मंच) के सहयोग से तैयार किया गया टेलीविज़न आधारित कार्यक्रम है।

### *SMILE के साथ फ़ील्ड के अनुभव*

राजस्थान के दस ज़िलों में, पचास सरकारी स्कूलों के साठ शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ गुणात्मक बातचीत की गई। कोविड-19 के प्रतिबन्धों के कारण, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ऑनलाइन और फ़ोन के माध्यम से चर्चा हुई।

समग्र शिक्षा अभियान (SamSA) के अधिकारियों द्वारा ज़िला शिक्षा अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से SMILE कार्यक्रम की शुरुआत की गई। SMILE कार्यक्रम को बॉक्स में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार लागू किया जाना था।

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण संस्थान, SMILE के लिए नोडल एजेंसी है। विभिन्न वर्गों के लिए ई-सामग्री निम्नलिखित स्थानों से आती है : एनसीईआरटी की वेबसाइट, *ई-पाठशाला, दीक्षा* (DIKSHA) कार्यक्रम और अन्य मुक्त स्रोत। विषय के शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ प्रारूप में अतिरिक्त सामग्री भी अपलोड कर रहे हैं।

**SMILE के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश**

- ई-सामग्री को राज्य स्तर पर स्कूल शिक्षा विभाग *व्हाट्सएप* ग्रुप पर अपलोड किया जाएगा; इसे आगे मुख्य ज़िला शिक्षा अधिकारी (CDEO) ग्रुप को भेजा जाएगा, वहाँ से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ग्रुप (CBEO) और फिर पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) ग्रुप या शहरी क्षेत्रों में नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक (FTB) नोडल अधिकारी को भेजा जाएगा।
- सभी PEEOs व्हाट्सएप ग्रुप के ग्रुप एडमिन होंगे। वे दो *व्हाट्सएप* ग्रुप बनाएँगे - एक शिक्षक का और दूसरा माता-पिता का।
- वीडियो की मदद से ऑनलाइन शिक्षण शुरू किया जाएगा।
- सामग्री सुबह 8 बजे CDEO ग्रुप पर अपलोड की जाएगी और फिर ब्लॉक स्तर CBEO ग्रुप को उपलब्ध कराई जाएगी।
- अगले दिन का दक्षता कार्यक्रम पिछली शाम को साझा किया जाएगा।
- केवल PEEO ही ग्रुप में सन्देश अपलोड कर सकते हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि केवल शैक्षिक सामग्री ही व्हाट्सएप ग्रुपों में साझा की जाए।
- CBEO, ट्रैकर शीट में *व्हाट्सएप* ग्रुप के विवरण अपलोड करेंगे।
- गूगल शीट को अपडेट करने की ज़िम्मेदारी CBEO पर है।
- शिक्षक राज्य स्तर पर अपनी सामग्री भी प्रस्तुत कर सकते हैं।
- RSCERT सामग्री तैयार करने के लिए नोडल एजेंसी है; सभी DIETs से यह अपेक्षा की जाती है कि वे ई-सामग्री की तैयारी और समीक्षा में अपना समर्थन दें।
- 40% से कम प्रविष्टियों वाले ज़िलों को अपने प्रदर्शन में सुधार करना चाहिए।
- विभाग का लक्ष्य इस पहल के माध्यम से सरकारी स्कूलों में नामांकित सभी बच्चों तक पहुँचना है।

*(ज़िला अधिकारियों के साथ SPD (SamSa) द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग के कार्य विवरण का सार, अप्रैल 2020)*

**बच्चों की संलग्नता**

ऑनलाइन संसाधनों का लाभ उठाने के लिए पहला क़दम है कार्यक्रम से लिंक स्थापित करना। फ़ील्ड के अनुभव और अनुक्रियाओं से संकेत मिलता है कि राजस्थान के अधिकांश ज़िलों में ऑनलाइन संसाधनों और विधाओं तक पहुँच एक चुनौती बनी हुई है।

विद्यार्थियों से हुई बातचीत बताती है कि पुराने विद्यार्थी और वे विद्यार्थी जो महत्त्वपूर्ण बदलाव के चरणों में हैं, अपने भविष्य के बारे में चिन्तित हैं। वे कोचिंग कक्षाओं में नहीं जा पा रहे या लाइब्रेरी तक नहीं पहुँच पा रहे। कुछ विद्यार्थी इस बात से नाख़ुश थे कि आवाजाही पर लगी रोक के कारण वे अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते, पढ़ाई के बारे में उनसे सलाह नहीं ले सकते और न ही खेलने के लिए बाहर जा सकते हैं। विद्यार्थियों ने कहा कि कक्षा-शिक्षक ने उनके माता-पिता (ज़्यादातर पिता) से सम्पर्क किया था और पूछा था कि क्या वे अपने बच्चों को SMILE से जोड़ने के लिए तैयार हैं। शिक्षक पूरी प्रक्रिया की व्याख्या करते और माता-पिता से सहमति मिलने पर व्हाट्सएप ग्रुप में फ़ोन नम्बर जोड़ देते। कुछ ज़िलों के ग्रामीण स्कूलों के विद्यार्थियों की शिकायत थी कि शिक्षकों ने समय पर ऑनलाइन कक्षाओं के सम्बन्ध में जानकारी साझा नहीं की। उन्होंने बताया कि उन्हें अध्ययन करने और SMILE से जुड़ने की इच्छा थी, लेकिन स्मार्टफ़ोन, इंटरनेट पैकेज और बैंडविड्थ न होने के कारण इस कार्यक्रम का लाभ उठाना मुश्किल था। उनके लिए पाठ देखना तभी सम्भव होता था, जब उन्हें कोई फ़ोन उपलब्ध होता था।

*सारे पाठ मेरे भाई के फ़ोन पर आते हैं। मैं उन्हें तभी देख पाती हूँ जब मेरा भाई काम से घर लौटता है। मैं हर रोज़ पाठ नहीं देख पाती हूँ।*

*हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए फ़ोन खरीदना सम्भव नहीं है। (कक्षा बारहवीं की छात्रा, दौसा)*

*कार्यक्रम*

यह सामग्री *व्हाट्सएप* ग्रुप पर रोज़ाना सुबह 9 बजे अपलोड की जाती है। वीडियो/ऑडियो/पीडीएफ फॉर्मेट में कक्षावार पाठ भेजे जाते हैं। विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि

वे पाठ देखें और नोट्स बनाएँ। यदि पाठ लम्बा हो तो उसे दो दिनों में विभाजित किया जाता है। चूँकि विद्यार्थियों के पास नई कक्षा की पाठ्यपुस्तकें नहीं थीं, इसलिए एक ज़िले में, हिन्दी और संस्कृत की पूरी पाठ्यपुस्तकें अपलोड की गईं। हाल ही में वर्कशीट देना भी शुरू किया गया है और विद्यार्थियों को घर पर करने के लिए कार्य भी दिए गए हैं। विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि यदि वे किसी पाठ को समझ नहीं पा रहे हों तो वे विषय के अध्यापकों से सम्पर्क करें।

*हमें इस तरीक़े से कभी नहीं पढ़ाया गया है, इसलिए हमारे लिए पाठ समझना आसान नहीं है। स्कूल में शिक्षक से सीखना कितना आसान होता है! (एक विद्यार्थी)।*

जहाँ विद्यार्थियों को सीखने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता हो, वहाँ यह सुनिश्चित कर पाना कि वे ख़ुद पढ़कर और बिना मार्गदर्शन के ही सीख लें, अव्यावहारिक लगता है।

*जेंडर-विषमताएँ*

घरों के भीतर जेंडर आधारित भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों के मद्देनज़र डिजिटल उपकरणों तक, सभी जेंडर की समान पहुँच भी एक महत्त्वपूर्ण पहलू है। शहरी क्षेत्रों में शिक्षकों ने बताया कि लड़कियाँ काफ़ी प्रयास कर रही थीं और जिन लड़कियाँ की पाठ तक पहुँच बन पा रही थी उन्हें अगर कुछ समझने में दिक़्क़त पेश आती थी तो वे अक्सर फ़ोन किया करती थीं।

लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की मोबाइल फ़ोन तक पहुँच कम है क्योंकि माता-पिता लम्बे समय तक अपने मोबाइल फ़ोन उन्हें देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उनको इस बात का डर है कि उनकी बेटियों को इंटरनेट पर 'ग़लत' जानकारी मिल सकती है या वे सहेलियों से बातें करने लगेंगी।

**शिक्षक-दृष्टिकोण**

शहरी और ग्रामीण दोनों स्कूलों में शिक्षकों का मानना था कि महामारी के दौरान शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हुई है। उन्हें डर था कि जब स्कूल फिर से खुलेंगे, तो कुछ विद्यार्थियों को पढ़ाई में कठिनाई महसूस होगी। शिक्षकों ने स्कूलों में ड्रॉपआउट दरों में वृद्धि की आशंका भी प्रकट की क्योंकि प्रवासी परिवारों के कई बच्चे अपने माता-पिता के साथ अपने गृहनगर चले गए थे।

शिक्षकों ने बताया कि SMILE का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा से जोड़ना और सीखना सुनिश्चित करना था जिससे *'पढ़ाई के प्रति रुझान रहे '*। कुछ शिक्षकों ने महसूस किया कि यह पहल फ़ायदेमन्द है क्योंकि इससे पढ़ाई में निरन्तरता सुनिश्चित हुई और लॉकडाउन की अवधि का उपयोग रचनात्मक रूप से किया जा रहा था। ऑनलाइन मंच के कारण सीखने में बच्चों की रुचि बनी रही। कुछ ग्रामीण स्कूली शिक्षकों ने, साफ़ तौर पर तो नहीं, लेकिन कहा कि लम्बी अवधि में SMILE की व्यवहार्यता के बारे में वे निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने महसूस किया कि डिजिटल सेवाओं और इंटरनेट कनेक्टिविटी के अभाव में ऑनलाइन अधिगम केवल आंशिक रूप से प्रभावी होगा।

शिक्षकों ने बताया कि कोविड-19 के दौरान ज़्यादातर मामलों में, माता-पिता को अपनी आजीविका के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है। ऐसे में सिर्फ़ बच्चों के ही उपयोग के लिए स्मार्टफ़ोन और इंटरनेट का ख़र्च उठाना उनके लिए मुश्किल है। शिक्षकों ने महसूस किया कि जब कार्यक्रम शुरू किया गया था तो विभाग को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था।

*हमारे स्कूल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियाँ अधिक हैं। माता-पिता के पास स्मार्टफ़ोन खरीदने के लिए धन नहीं है; इंटरनेट कनेक्टिविटी अनिश्चित है; कई क्षेत्रों में बिजली भी नहीं है।* (शिक्षक, बारां)

शिक्षकों (शहरी और ग्रामीण दोनों) के अनुमान के अनुसार वे जितने विद्यार्थियों के साथ जुड़ सके, उनका प्रतिशत स्कूलों में कुल नामांकन का 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक है। कई अभिभावकों के फ़ोन नम्बर उपलब्ध नहीं थे। शिक्षकों का विचार था कि इस पहल को बिना पूर्व-सूचना और तैयारी के लागू किया गया था। ज़िला/ब्लॉक के अधिकारियों और शिक्षकों ने केवल राज्य या ज़िला स्तर से मिलने वाले आदेशों का पालन किया। उन्मुखीकरण की कमी बाधा बन रही है क्योंकि कई शिक्षक दूरस्थ शिक्षा के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग से परिचित नहीं हैं। वैसे हाल ही में शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षण और अधिगम के कौशलों से लैस करने के लिए कुछ प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त शिक्षकों को रोज़ पाँच विद्यार्थियों से सम्पर्क करना होता है और पाठों पर फ़ीडबैक लेना होता है। शिक्षकों को गूगल फॉर्म के दो सेट भरकर अपलोड करने होते हैं – एक, कॉल के विवरण रिकॉर्ड करने के लिए और दूसरा ई-सामग्री पर शिक्षक के सुझावों को जानने के लिए। यह दोनों मशीनी और समय लेने वाले कार्य हैं। एक राज्य अधिकारी ने टिप्पणी की कि ज़िलों में शिक्षकों के फ़ीडबैक की स्थिति असमान है।

शिक्षकों ने महसूस किया कि सरकारी स्कूलों में डिजिटल अधिगम पर ज़ोर देने से डिजिटल विभाजन बढ़ गया है क्योंकि सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में विद्यार्थी कई कारणों से इसमें भाग नहीं ले पा रहे हैं।

## निष्कर्ष

ऊपर चर्चित डिजिटल अधिगम का अनुभव SMILE कार्यक्रम की छिटपुट पहुँच को दर्शाता है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में यह अन्तराल स्पष्टतया दिखाई देते हैं। समस्या इस धारणा में थी कि यह मान लिया गया कि केवल एक सरकारी आदेश से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों की अत्यधिक विषम जनसंख्या के लिए ऑनलाइन अधिगम की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है; वह भी ऐसी स्थिति में जब चारों ओर तनाव और अभाव है और इन लोगों से यह अपेक्षा की गई कि वे आवश्यक समर्थन और तैयारी के बिना ही इस नए तरीक़े को अपनाकर उस आदेश का अनुपालन करें।

यदि ऑनलाइन सीखने की पहल का वांछित प्रतिफल सीखने में निरन्तरता प्रदान करना है, तो *व्हाट्सएप* के माध्यम से सामग्री/पाठों के प्रावधान और वितरण को अकादमिक जुड़ाव या गुणवत्तापूर्ण अधिगम के बराबर नहीं माना जा सकता। विद्यार्थियों का अनुभव बताता है कि विभिन्न बाधाओं का सामना करने के कारण ऑनलाइन सामग्री का इस्तेमाल करना आसान नहीं है।

जिस राज्य में शैक्षिक चुनौतियाँ बहुत होती हैं, वहाँ यह आवश्यक है कि बच्चों के अधिगम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समन्वित रणनीतियों का एक विवेकपूर्ण मिश्रण हो, जो विद्यार्थियों के सामाजिक, आर्थिक और संरचनात्मक अवरोधों को सम्बोधित करे। जो बच्चे ग़रीब परिवारों से आते हैं, उनमें अभाव की जो भावना पैदा होती है, वह उनके स्वास्थ्य और शिक्षा पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकती है। कई विद्यार्थी शैक्षिक धारा से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। शैक्षिक योजनाकारों और प्रबन्धकों को चाहिए कि वे इन सरोकारों को सम्बोधित करें और आने वाले समय में अधिक समावेशी, कुशल और लचीली शिक्षा प्रणालियों के निर्माण की दिशा में काम करें।

***आभार***

*लेखिकाद्वय सोमोती लाल, सुनील शेखर, उषा और भंवर के प्रति आभारी हैं कि उन्होंने विभिन्न ज़िलों में शिक्षक और विद्यार्थियों के साथ बातचीत में मदद की।*

**शोभिता राजगोपाल** विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर, राजस्थान में एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं। उन्हें सामाजिक विकास व नीति अनुसन्धान, प्रशिक्षण और नीति सलाह के क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने राजस्थान और भारत की शैक्षिक प्रक्रियाओं में जेंडर-विषमताओं को समझने के क्षेत्र में व्यापक रूप से काम किया है। वर्तमान में वे CORTH, यूनिवर्सिटी ऑफ़ ससेक्स द्वारा शुरू किए गए 'ब्लड नैरेटिव्स' पर काम करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्क ऑफ रिसर्चर्स से सम्बद्ध हैं। हाल ही में उन्होंने 'ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इन सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन इन इंडिया', Routledge, 2019 शीर्षक पुस्तक का सह-लेखन किया है। उनसे **shobhiraj@hotmail.com** पर सम्पर्क किया जा सकता है।

**मुक्ता गुप्ता** बीस वर्षों से भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया में एक शिक्षक-प्रशिक्षक हैं। पिछले छह वर्षों से वे जेंडर और शिक्षा से सम्बन्धित मुद्दों पर एक स्वतंत्र शोधकर्ता के रूप में कार्य कर रही हैं। उन्होंने भारत में, ख़ासकर राजस्थान में, हाशिए के समुदायों के लाइफ स्किल एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने राजस्थान सरकार के लिए अध्यापिका मंच और मीना मंच मॉड्यूल विकसित करने में यूनिसेफ़ के साथ मिलकर कार्य किया है। वे लड़कियों के स्वास्थ्य और शिक्षा से सम्बन्धित परियोजनाओं में कई संगठनों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि दूसरा दशक, विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर और सन्धान। उनसे **mukta.gupta66@gmail.com** पर सम्पर्क किया जा सकता है।

**अनुवाद :** नलिनी रावल